भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4422
जिसका उत्तर 20 अगस्त, 2025 को दिया जाना है।
29 श्रावण, 1947 (शक)

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अगले चरण में एआई और एमएल का समावेश

4422. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवालः

क्या इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार आगामी वर्षों में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का दायरा बढ़ाने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार लाने के उद्देश्य से कोई नई पहल की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अगले चरण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) में प्रगति शामिल किए जायेंगे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार की डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार के माध्यम से डिजिटल साक्षरता बढ़ाने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में डिजिटल बुनियादी ढांचे के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए निजी क्षेत्र के साथ और अधिक सहयोग शामिल होगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क): प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप, सरकार ने प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण और नागरिकों को सशक्त बनाने हेतु डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम तीन प्रमुख विजन क्षेत्रों पर केंद्रित है: प्रत्येक नागरिक के लिए एक प्रमुख उपयोगिता के रूप में डिजिटल अवसंरचना, मांग के आधार पर गवर्नेंस और सेवाएँ, और नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण। पिछले 11 वर्षों में, इसने भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज को पूरी तरह रूपांतरित कर दिया है।

डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (**डीपीआई**): औद्योगिक विकास के लिए पारंपरिक अवसंरचना की तरह, यह डिजिटल अर्थव्यवस्था को बदलने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसकी प्रमुख उपलब्धियों में आधार, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफ़ेस (यूपीआई), डिजिलॉकर, उमंग आदि शामिल हैं।

आधार: 142 करोड़ से अधिक निवासियों को डिजिटल पहचान प्रदान की गई है।

प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई): प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत 55 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए।

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई): 49 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता और 675 बैंक यूपीआई से जुड़ चुके हैं, जिससे यह दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल भुगतान प्रणाली बन गई है।

सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी): ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल सेवाएँ प्रदान करने के लिए सीएससी स्थापित किए गए हैं। देश भर में (ग्रामीण+शहरी) 5.60 लाख से अधिक सीएससी कार्यरत हैं, जिनमें से 4.36 लाख सीएससी ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत हैं।

कनेक्टिविटी: देश में भारतनेट परियोजना के अंतर्गत 2.14 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार किया गया है।

अगस्त, 2023 में**,** सरकार ने 15वें वित्त आयोग की अवधि**,** यानी 2021-22 से 2025-26 तक, ₹14**,**903.25 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार को स्वीकृति दी। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

(i) इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी उद्योग के विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
(ii) डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना/प्लेटफार्मों और डिजिटल समावेशन के माध्यम से नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना।
(iii) शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों तथा सरकारी संस्थानों को उच्च गति की कनेक्टिविटी प्रदान करना।
(iv) इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर में विनिर्माण क्षमताओं और आत्मनिर्भरता के विकास को बढ़ावा देना।
(v) आईटी क्षेत्र में भारत की ताकत, विघटनकारी नवाचारों और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए एक स्थायी सॉफ्टवेयर उद्योग के निर्माण को बढ़ावा देना।
(vi) सुपरकंप्यूटिंग, क्वांटम प्रौद्योगिकी, ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि सहित प्रमुख और अनुप्रयुक्त क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देना।
(vii) देश में साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर लगभग वास्तविक समय साइबर सुरक्षा स्थितिजन्य जागरूकता पैदा करना।
(viii) डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना और लेनदेन में पारदर्शिता लाना।

(ख): कनेक्टिविटी: देश की सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) और गाँवों को उच्च बैंडविड्थ क्षमता वाली इंटरनेट/ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना। दूरसंचार विभाग (डीओटी) भारतनेट परियोजना को चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित कर रहा है। देश में भारतनेट परियोजना के अंतर्गत 2.14 लाख से अधिक जीपी को सेवा के लिए तैयार किया जा चुका है। इसके अलावा, देश भर के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में **5जी सेवाएँ** शुरू कर दी गई हैं और यह देश के 99.9% जिलों में उपलब्ध है। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा देश भर में 4.86 लाख से अधिक 5जी बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बीटीएस) स्थापित किए जा चुके हैं।

(ग): इंडिया एआई मिशन: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप**,** सरकार प्रौद्योगिकी में नवाचारों का नेतृत्व कर रही है और इसे सभी के लिए सुलभ बना रही है। वास्तविक दुनिया की समस्याओं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के विकास और उपयोग को लोकतांत्रिक बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जिससे अंततः विभिन्न क्षेत्रों में जीवन में सुधार होगा।

इंडियाएआई मिशन में 7 प्रमुख स्तंभ शामिल हैं, अर्थात् इंडियाएआई कंप्यूट कैपेसिटी, इंडियाएआई फाउंडेशन मॉडल, एआईकोश , इंडियाएआई एप्लिकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव , इंडियाएआई फ्यूचरस्किल्स , इंडियाएआई स्टार्टअप फाइनेंसिंग और सुरक्षित एवं विश्वसनीय एआई।

इंडियाएआई मिशन में लक्षित हस्तक्षेप शामिल हैं, जो अन्य बातों के साथ-साथ जवाबदेही, सुरक्षा, निष्पक्षता और मानवाधिकारों एवं गोपनीयता की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।

(घ): "प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा)" के अंतर्गत देश भर में 6.39 करोड़ व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया। इसके अतिरिक्त, फ्यूचरस्किल्स प्राइम कार्यक्रम के अंतर्गत , अब तक 22.9 लाख से अधिक अभ्यर्थी पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं, जिनमें से 13.8 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकन कराया है। इसके अतिरिक्त, 18,785 सरकारी अधिकारियों, 2,367 प्रशिक्षकों और 19,929 छात्रों (208 बूटकैंप के अंतर्गत) को सी-डैक और नाइलिट केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया है।

(ङ): हाल के वर्षों में भारत की डिजिटल अवसंरचना में व्यापक परिवर्तन आया है, जिसने देश को डिजिटल एडॉप्शन में वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित किया है। क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), मशीन लर्निंग (एमएल) और डिजिटल गवर्नेंस में नवाचारों द्वारा संचालित, तेज़ी से विस्तारित डिजिटल अर्थव्यवस्था के साथ, भारत की अवसंरचना सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की बढ़ती माँगों को पूरा करने के लिए निरंतर विकसित हो रही है। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) औद्योगिक विकास के लिए पारंपरिक अवसंरचना की तरह ही डिजिटल अर्थव्यवस्था को बदलने में सहायक रही है। प्रमुख उपलब्धियों में आधार, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई), डिजिलॉकर, उमंग आदि शामिल हैं। यूपीआई सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के बैंकों और मोबाइल वॉलेट सेवा प्रदाताओं के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। आधार (सुशासन के लिए प्रमाणीकरण) नियम, 2020 को वर्ष 2025 में विशेष रूप से संशोधित किया गया है, ताकि निजी क्षेत्र की कंपनियों को विशिष्ट उद्देश्यों, मुख्यतः जनहित, नवाचार और सेवाओं तक पहुँच में सुधार से संबंधित, के लिए आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करने की अनुमति मिल सके। डिजिलॉकर और एंटिटी लॉकर में निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों के जारीकर्ता और अनुरोधकर्ता संगठन भी शामिल हैं। अन्य महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म में सरकारी खरीद के लिए गवर्मेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) शामिल है, जो निजी क्षेत्र के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करता है।

***